THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BALLU): (a) and (b) The Southern States of Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala, Pondicherry and Tamilnadu have appointed the Kerala State Industrial Development Corporation (KSIDC) as the nodal agency for preparing a pre-feasibility report for the Southern Gas Grid project. The percentages of gas to be drawn by the States have not been decided.

(c) and (d) The pre-feasibility study admmissioned by KSIDC has recently been completed. It has been estimated in the study that the project cost may lie between Rs. 6000 crores to Rs. 12,000 crores for different alignements and capecities.

Dobhol Power Project

545. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have since approved and signed a counter guarantee with regard to the Dabhol Power Project, as per the revised terms of agreement signed between the Government of Maharashtra and the Enron Company; and

(b) what are the main modifications and changes made in the original agreement under the revised terms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं संबंधी राष्ट्रीय नीति

546. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों, भूमिगत नालियों का निर्माण और सफाई एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाये प्रदान करने हेतु कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र देव प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु राष्ट्रीय नीति का निर्धारण केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण, शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना, महिलाओं के लिए विशेष स्वच्छता परिसरों का निर्माण, ऊपरी नालियों के निर्माण द्वारा गांव की पूर्ण स्वच्छता, सोख्ता गड्ढों, मल-मूत्र का निपटान, व्यक्तियों में अनुभूत आवश्यकताओं एवं जागरूकता सृजन के लिए गहन अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक स्वच्छता सुविधाओं के लिए किया गया है।

(ग) उपर्युक्त गतिविधियां राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में उपलब्ध परिव्यय के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं। पारिवारिक शौचालयों का निर्माण लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा वित्तपोषित स्वयं सेवी संगठनों द्वारा भी किया जाता है। 1996-97 के लिए अन्तिम परिव्यय केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 60.00 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 102.53 करोड़ रुपए है।

Scarcity of Potable Water in small and medium Towns in Karnataka

547. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have identified small and medium towns in Karnataka where there is perennial scarcity of drinking water;

(b) if so, the names of such towns as on 30th June, 1996;